



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.147-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016 (BHADRA 18, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2016

संख्या 13/1/2015-3टी(1).— हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधित करने के लिए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार द्वारा नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- ये नियम हरियाणा मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।
- हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 60 में, “नवीनीकरण” शब्द जहां कहीं भी आए के बाद, “या अन्तरण” शब्द रखा जाएगा।
- उक्त नियमों में, नियम 61 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“61. परमिट प्रदान करने, नवीकरण करने तथा प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए शुल्क। [धारा 96(2)(vii) और (xxiii)].—

(1) परमिट प्रदान करने तथा नवीकरण करने के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा, अर्थात्:—

(क) दुपहिया/तिपहिया यानों हेतु —	
पाँच वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क	— एक हजार रुपये
एक वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क	— दो सौ पचास रुपये;
(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित यानों से अन्यथा हल्के मोटरयानों हेतु —	
पाँच वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क	— तीन हजार पांच सौ रुपये
एक वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क	— आठ सौ रुपये;
(ग) अन्य मोटरयानों हेतु —	
पाँच वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क	— पांच हजार दो सौ पचास रुपये

- एक वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क — एक हजार दो सौ रुपये
- (2) परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा :—
- (क) दुपहिया/तिपहिया यानों हेतु—
एक वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क — दो सौ पचास रुपये
- (ख) उपरोक्त (क) में वर्णित यानों से अन्यथा हल्के मोटरयानों हेतु—
एक वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क — आठ सौ रुपये
- (ग) अन्य मोटरयानों हेतु—
एक वर्ष के लिए सम्पूर्ण राज्य हेतु भुगतानयोग्य शुल्क — एक हजार दो सौ रुपये

परन्तु भारत में विदेशी दूतावासों को उनके स्वामित्व वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में प्रदान किए गए किसी परमिट के लिए कोई भी शुल्क भुगतानयोग्य नहीं होगा।

(3) यदि जहाँ मोटरयान परमिट के बिना रहा है, तो पचास रुपये तथा प्रति सप्ताह सौ रुपये और के अध्यक्षीन उसके भाग उसके भाग की शास्ति सहित अधिकतम एक हजार दो सौ पचास रुपये अस्थाई परमिट फीस तक उक्त दुपहिया/तिपहिया तथा एवं अन्य वाहनों से क्रमशः परमिट प्रदान/नवीकरण करते समय प्रभारित की जाएगी। यदि वाहन वैध परमिट के बिना संचालित किया जा रहा पाया जाता है, तो मोटरयान अधिनियम, 1988, 1988 का 59, की धारा 192-क के उपबंध का आह्वान किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 62 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) यदि जहाँ मोटरयान अस्थाई परमिट के बिना रहा है, तो पचास रुपये तथा प्रति सप्ताह सौ रुपये और अधिकतम एक हजार दो सौ पचास रुपये तो अध्यक्षीन उसके भाग की शास्ति सहित अस्थाई परमिट फीस क्रमशः दुपहिया/तिपहिया तथा अन्य वाहनों से क्रमशः उक्त अस्थाई परमिट प्रदान करते समय प्रभारित की जाएगी। तथापि, यदि वाहन वैध परमिट के बिना संचालित किया जा रहा पाया जाता है, तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192-क के उपबंध का आह्वान किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 74 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“74.परमिट अन्तरण। [धारा 82 तथा धारा 96(2) (vii) और (ix)].—(1) परमिट के अन्तरण के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा,—

- (क) दुपहिया/तिपहिया यानों हेतु— — दो सौ रुपये
- (ख) उपरोक्त (क) में वर्णित यानों से अन्यथा हल्के मोटरयानों हेतु — पांच सौ रुपये
- (ग) अन्य यानों हेतु — एक हजार रुपये :

परन्तु परमिट के अन्तरण की दशा में, इस प्रकार अन्तरित परमिट उसकी समाप्ति की तिथि तक वैध रहेगा। आगे, परमिट धारक की मृत्यु की दशा में परमिट कोई शुल्क प्रभारित किए बिना मृतक के कानूनी वारिस को अन्तरित हो जाएगा और ऐसा परमिट उसकी समाप्ति की तिथि तक वैध रहेगा।

(2) जब परमिट धारक धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को परमिट अन्तरित करने का इच्छुक है, तो वह उस व्यक्ति को जिसे वह अन्तरण करने का इच्छुक है, लिखित में संयुक्त आवेदन परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को विहित शुल्क के साथ अन्तरण के कारणों का उल्लेख करते हुए देगा।

- (3) (i) यदि उप-नियम (1) के अधीन किसी परमिट के अन्तरण की अनुमति रखने वाले परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी की बाद में संतुष्टि हो जाती है कि आवेदन के तथ्य, जिन पर अन्तरण अनुज्ञात किया गया था, असत्य या अधूरे थे, तो यह पक्षकारों को सुनने के उपरांत अन्तरण को अमान्य घोषित करेगा तथा परमिट की वैधता, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए अन्तरिती दायी हो सकता है, समाप्त हो जाएगी।
- (ii) परमिट धारक की मृत्यु की दशा में, परमिट धारक के कानूनी वारिस (वारिसों) उप-नियम (1) के अधीन परमिट के अन्तरण हेतु आवेदन परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा आवेदन के साथ परमिट के भाग—क तथा ख परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी को सुपुर्द करेगा;
- (iii) परमिट के भाग—क तथा ख की प्राप्ति पर, परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी, उस पर धारक के विवरणों को रद्द करेगा और अन्तरिती के विवरण पृष्ठांकित करेगा और अन्तरिती को परमिट वापिस लौटा देगा;

- (iv) यथा उपरोक्त परमिट का अन्तरण करते हुए परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जिसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा परमिट प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, से अन्यथा अपेक्षित हो, परमिट के भाग—क तथा ख को अतिरिक्त क्षेत्र या मार्ग, जिसके लिए परमिट प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, “के लिए मान्य ———” शब्दों के साथ पृष्ठांकन करेगा;
- (v) जब तक खण्ड (iii) में यथा उपबन्धित परमिट के भाग—क तथा ख को पृष्ठांकित नहीं किया गया हो अथवा जब तक खण्ड (iv) में यथा उपबन्धित परमिट प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले प्राधिकरण द्वारा परमिट के अन्तरण हेतु पृष्ठांकन को अनुमोदित नहीं किया गया हो, तो अन्तरण की तिथि के बाद ऐसे प्रतिहस्ताक्षर का कोई प्रभाव नहीं होगा।

व्याख्या.— “परमिट के अन्तरण का उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उदाहरणार्थ: एक परमिट जिसकी वैधता 30 जून, 2015 से 29 जून, 2020 तक है तथा 30 जून, 2016 को और आगे 30 जून, 2017 को अन्तरित किया जाता है, तो उसकी वैधता अन्तरण की संख्याओं पर ध्यान दिए बिना 29 जून, 2020 तक रहेगी।”

एस० एस० ढिल्लों,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 9th September, 2016

No. 13/1/2015-3T(1).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Transport Department, Chandigarh, with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2016.
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 60, after the word “renewal”, wherever occurring, the words “or transfer” shall be inserted.
3. In the said rules, for rule 61, the following rule shall be substituted, namely:—

“61. Fees for grant, renewal and countersignature of permits. [section 96(2) (vii) and (xxiii)].—

 - (1) The fee for grant and renewal of permits shall be as under:—

(a) Two/three- wheeled vehicles—	
Fee payable for the entire State for five years	—one thousand rupees
Fee payable for the entire State for one year	—two hundred and fifty rupees
(b) Light Motor Vehicles other than vehicles mentioned at (a) above—	
Fee payable for the entire State for five years	—three thousand five hundred rupees
Fee payable for the entire State for one year	—eight hundred rupees
(c) Other motor vehicles—	
Fee payable for the entire State for five years	— five thousand two hundred fifty rupees
Fee payable for the entire State for one year	— one thousand two hundred rupees

(2) The fees for countersignature of permits shall be as under:-

- | | | |
|-----|--|----------------------------------|
| (a) | Two/three-wheeled | |
| | Fee payable for the entire State for one year | – two hundred and fifty rupees |
| (b) | Light Motor Vehicles other than vehicles mentioned at (a) above- | |
| | Fee payable for the entire State for one year | –eight hundred rupees |
| (c) | Other motor vehicles- | |
| | Fee payable for the entire State for one year | –one thousand two hundred rupees |

Provided that no fee shall be payable for a permit granted to foreign embassies in India in respect of transport vehicles owned by them.

(3) In case where a motor vehicle remained without permit, temporary permit fee along with penalty of Rs.50/- and Rs.100/- per week and part thereof subject to maximum Rs.1250/- shall be charged from two/three-wheeled vehicles and other vehicles respectively at the time of grant/renewal of said permit. However, in case a vehicle is found plying without valid permit, the provisions of section 192-A of Motor Vehicles Act, of 1988 shall be invoked.

4. In the said rules, in rule 62, for sub-rule (2), the following sub-rule, shall be substituted, namely:-

“In case where a motor vehicle remained without temporary permit, a fee for temporary permit along with penalty of Rs.50/- and Rs.100/- per week and part thereof subject to maximum Rs.1250/- shall be charged from two/three-wheeled vehicles and other vehicles respectively at the time of grant/renewal of said permit. However, in case a vehicle is found plying without valid permit, the provisions of section 192-A of Motor Vehicles Act, of 1988 shall be invoked.”

5. In the said rules, for rule 74, the following rule, shall be substituted, namely:-

“74. Transfer of permit. [section 82 and 96(2) (vii) and (ix)] (1) The fees for transfer of permit shall be as under:-

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| (a) | Two/three-wheeled vehicles | –two hundred rupees |
| (b) | Light Motor Vehicles other than vehicles mentioned at (a) above- | –five hundred rupees |
| (c) | Other motor vehicles | –one thousand rupees |

Provided that in case of transfer of permit, the permit so transferred shall remain valid till its expiry date. Further, in case of death of the permit holder, the permit shall be transferred to the legal heir of the deceased without charging any fee and such permit shall remain valid till its expiry date.

(2) When the holder of a permit desires to transfer the permit to some other person under Sub-section (1) of Section 82, he and the person to whom he desires to make the transfer shall make a joint application in writing accompanied by the fee prescribed to the permit issuing authority, setting forth the reasons for the transfer.

- (3) (i) If the permit issuing authority having permitted any transfer of a permit under sub-rule (1) is subsequently satisfied that the contents of the application on which the transfer was allowed were false or incomplete, it may after hearing the parties shall thereupon, declare the transfer to be void and the permit shall thereupon, without prejudice to any other penalty to which the transferee may be liable, cease to have validity.
- (ii) In case of death of the permit holder, the legal heirs of the permit holder shall submit an application to the permit issuing authority for transfer of permit under sub-rule (1) and shall handover Part-A and B of the permit to the permit issuing authority along with the application.
- (iii) Upon receipt of Parts A and B of the permit, permit issuing authority shall cancel the particulars of the holder thereon, and endorse particulars of the transferee and shall return the permit to the transferee.
- (iv) The permit issuing authority making a transfer of a permit as aforesaid may, unless any other State or Regional Transport Authority by which the permit has been countersigned by general or special order has otherwise required, endorse Parts A and B of the permit with the words "valid for ---" inserting the name of the extra area or route for which the permit has been countersigned.

- (v) Unless Parts A and B of the permit have been endorsed as provided in clause (iii) or unless the transfer of a permit has been approved by endorsement by the authority which countersigned the permit as provided in clause (iv), the countersignatures shall be of no effect after the date of transfer.

Explanation:- "The transfer of a permit shall have no effect on its validity. For example: A permit having validity from 30th June, 2015 to 29th June, 2020 and is transferred on 30th June, 2016 and further transferred on 30th June, 2017 then the same shall remain valid up to 29th June, 2020 irrespective of number of transfers."

S. S. DHILLON,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Transport Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 सितम्बर, 2016

संख्या 11/5/2013-4श्रम- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मैसर्स रेनान इलैक्ट्रिक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं० 280, सैक्टर-7, आई०एम०टी०, मानेसर, जिला गुडगांव, हरियाणा के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं 7-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे के बीच दो शिफ्टों में महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके, अर्थात्:-

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा न ही उसे अनुमति दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी अथवा उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी महिला कर्मकार को, जो सायं 7.00 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि के दौरान काम करने से इन्कार करती है, तो उसे इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जायेगा अथवा अलग नहीं किया जायेगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिये अकेला नहीं लगाया जायेगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापिस ले जाने वाले प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिये क्रेच का प्रावधान तथा रखरखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदली जाएगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और वापस जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यवस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10 बजे तक दूसरी शिफ्ट में कार्य के लिए बुलाया जाता है।
10. कारखाना की केन्टीन में महिला कर्मकारों के लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सकें।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गये न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए.आई.आर. 1997 सर्वोच्च न्यायालय-3011) के निर्देश के निबन्धनों के अनुसार महिला कर्मकारों के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

डॉ० महावीर सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**LABOUR DEPARTMENT****Notification**

The 9th September, 2016

No. 11/5/2013-4Lab.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana hereby varies the limits laid down in clause (b) of Sub-section (1) of Section 66 of the said Act in respect of M/s Ryonan Electric India Private Limited, Plot No. 280, Sector-7, IMT Manesar, District Gurgaon, Haryana so as to authorize the employment of women workers from 7.00 p.m. to 10.00 p.m. in two shifts for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette subject to the following conditions, namely: -

1. No woman worker shall be required or allowed to work in the factory between 10.00 p.m. to 6:00 a.m.
2. No woman worker shall be required or allowed to work for more than 9 hours in a day and 48 hours in a week.
3. No woman worker who declines to work during the period 7.00 pm to 10.00 pm shall be removed from employment or discriminated on this account.
4. No woman worker shall be engaged alone to work in the second shift.
5. The free medical facility by engaging a doctor and a female nurse shall be provided to the women workers in the second shift.
6. The occupier shall provide lady security guard to accompany the women workers on each transportation vehicle for their safety.
7. The occupier shall maintain a 'Creche' for the use of children of women workers.
8. The shift of women workers shall be changed after a weekly holiday.
9. The company shall provide free transport facility to woman workers from their residence and back who are called to work in the second shift upto 10.00 p.m.
10. The arrangements for meal shall be made in the canteen of the factory so that the women workers can take their meals in the second shift.
11. The management shall ensure protection of women workers from sexual harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka and others *V/s* State of Rajasthan *vide* judgment dated 13th August, 1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).

DR. MAHAVIR SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.